एन. पी. पोन्नुस्वामी

बनाम

निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल चुनाव क्षेत्र और अन्य

भारत संघ और मध्य भारत राज्य - हस्तक्षेपकर्ता।

[पतंजलि शास्त्री, सी. जे., फजल अली, मेहर चंद महाजन, मुखर्जीया, दास और चंद्रसेखर अय्यर जे.]

भारतीय संविधान अनुच्छेद. 226, 324 से 329 तक- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा. 36, 80 - विधानमंडलों के चुनाव- नामांकन पत्र की अस्वीकृति - उत्प्रेषण–लेख के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन— संधार्यता- उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार- चुनाव का अर्थ और चुनाव पर सवाल उठाना "- चुनावों के संबंध में विधानमंडल की नीति- विशेष उपाय।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) प्रावधानित करता है कि " संसद के किसी भी सदन या सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए कोई चुनाव नहीं किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन को क्यू में बुलाया जाएगा। इस तरह के प्राधिकरण को प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के अलावा और ऐसी रीति से जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के लिए, उसके द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए। का प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम, 1951, जिसमें देश के विभिन्न विधानमंडलों के चुनाव के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए थे, में भी एक 'प्रावधान' शामिल है। प्रावधान (धारा 80) कि परंतुक के अनुसार प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के अलावा कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।अधिनियम के सिद्धांत।

अपीलार्थी, जो मद्रास राज्य की विधान सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार था और जिसका नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया था। अनुच्छेद के तहत मद्रास का न्यायालय। 226 निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश को निरस्त करने और निर्वाचन अधिकारी को सार्वजनिक किए जाने वाले वैध नामांकनों की सूची में उनका नाम शामिल करने का निर्देश देने के लिए संविधान के प्रमाण पत्र के लिए रिट:

पूर्ण पीठ द्वारा निर्णित (पतंजलि शास्त्री, सी. जे., फजल अली, महाजन, मुखर्जी, दास और चंद्रसेखर अय्यर जे.) कि संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और धारा 80 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, उच्च न्यायालय को निर्वाचन अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

लोकतांत्रिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में "चुनाव" शब्द का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, जिसका व्यापक और संकीर्ण दोनों अर्थ प्राप्त हुए हैं।

संकीर्ण अर्थ में इसका उपयोग उम्मीदवार के अंतिम चयन के लिए किया जाता है। जिसमें मतदान होने पर मतदान का परिणाम शामिल हो सकता है कोई मतदान नहीं। व्यापक अर्थों में, इस शब्द का उपयोग पूरे अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने की प्रक्रिया और यह इस व्यापक अर्थ में है कि इस शब्द का उपयोग एफ के भाग XV में किया गया है संविधान जिसमें अनुच्छेद 329 (बी) आता है।

संविधान के भाग XV की योजना और प्रतिनिधि ऐसा प्रतीत होता है कि लोक अधिनियम, 1951 किसी भी मामले पर लागू होता है। जिसका चुनाव को दूषित करने का प्रभाव पड़ता है, उसे लाया जाना चाहिए केवल उचित स्तर पर उचित तरीके से एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष और एक अंतर-न्यायालय में नहीं लाया जाना चाहिए किसी भी अदालत के समक्ष मध्यस्थता करें। चुनाव कानून के तहत, केवल नामांकन पत्र की अस्वीकृति का क्या महत्व है, इस तथ्य में शामिल है कि इसका उपयोग कॉल करने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है विचाराधीन चुनाव। अनुच्छेद 329 (बी) स्पष्ट रूप से अधिनियमित किया गया था यह किस तरीके से और किस स्तर पर होना चाहिए, यह निर्धारित करें। आधार, और अन्य आधार जो कानून के तहत उठाए जा सकते हैं विचाराधीन चुनाव को बुलाने का आग्रह किया जा सकता है। यह आवश्यकता के अनुसार होता है। इस प्रावधान की भाषा से गंभीर निहितार्थ है कि वे किसी अन्य स्तर पर किसी अन्य तरीके से आधार का आग्रह नहीं किया जा सकता है। और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष। यदि किस आधार पर। एक चुनाव प्रश्न में बुलाया जा सकता है एक प्रारंभिक चरण में उठाया जा सकता है और त्रुटियाँ, यदि कोई हों, सुधार ली जाती हैं, तो उन्हें लागू करने का कोई मतलब नहीं होगा। अनुच्छेद 329 (बी) जैसे प्रावधान और एक विशेष प्रावधान की स्थापना में न्यायाधिकरण "। में प्रयुक्त शब्दों का कोई अन्य अर्थ अनुच्छेद विसंगतियों को जन्म देगा, जो संविधान कर सकता है विचार नहीं किया है, उनमें से एक विरोधाभासी विचार है उच्च न्यायालय द्वारा मतदान पूर्व चरण में व्यक्त किया जा सकता है और चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा, जो एक स्वतंत्र निकाय होना है, वह अवस्था जब मामला उसके सामने लाया जाता है। इसलिए, नामांकन पत्र की अस्वीकृति पर सवाल उठाना "सवाल पूछना" है। संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के अर्थ के भीतर चुनाव टियोन और सेक। धारा 80 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।

कानून द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र को लोकतांत्रिक देशों में प्रदर्शन करना पड़ता है, यह हमेशा से रहा है चुनाव समाप्त होने तक राज्यों को स्थगित किया जाना चाहिए, इसलिए कि चुनाव की कार्यवाही अनुचित रूप से मंद न हो या लंबा। इस सिद्धांत के अनुरूप, की योजना इस देश के साथ-साथ इंग्लैंड में भी चुनाव कानून है कि नहीं महत्व किसी भी ऐसी चीज से जुड़ा होना चाहिए जो प्रभावित नहीं करती है। "चुनाव"; और यदि कोई अनियमितता की जाती है, तो यह है जो प्रगति पर है और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित हैं, जिसके तहत जिस कानून द्वारा चुनाव संचालित किए जाते हैं, उसका प्रभाव होगा "चुनाव" को दूषित करना और प्रभावित व्यक्तियों को सक्षम बनाना

इसे प्रश्न में कॉल करें, उन्हें एक विशेष के सामने लाया जाना चाहिए एक चुनाव याचिका के माध्यम से न्यायाधिकरण और नहीं बनाया जाएगा चुनाव के दौरान किसी भी अदालत के समक्ष विवाद का विषय प्रगति।

चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में मतदान करने या खड़े होने का अधिकार एक नहीं है उसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन। कड़ाई से बोलते हुए, यह सभी की जांच और निर्धारण करने का विधानमंडल का एकमात्र अधिकार है अपने सदस्यों के चुनाव से संबंधित मामले, और यदि विधायिका इसे अपने हाथों से निकालती है और एक विशेष कार्य में निहित होती है। न्यायाधिकरण एक पूरी तरह से नया और अज्ञात क्षेत्राधिकार, कि विशेष अधिकारिता का प्रयोग उस कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जो इसे बनाते हैं।

जहाँ एक कानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है जो देता है इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय, उसके द्वारा प्रदान किया गया उपाय केवल कानून का लाभ उठाया जाना चाहिए।

वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वाटर वर्क्स कंपनी। हॉक्सफोर्ड [6 ई. पू.], (एन. एस.) 336], नेविल बनाम लंदन एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड (1919) ए. सी. 368), अटॉर्नी-जनरल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो बनाम। गॉर्डन ग्रांट एंड कंपनी ([1935] ए. सी. 532), राज्य सचिव बनाम। मास्क एंड कंपनी (44 सी. डब्ल्यू. एन. 709), हुर्दुतराई बनाम। कलकत्ता का आधिकारिक कार्यभार (52) सी. डब्ल्यू. एन. 343), थेबर्ग बनाम। लॉड्री (1876,2 ऐप। कैस। 102) संदर्भित किया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय ने पुष्टि की।

न्यायनिर्णय: मामला संख्या 351 सिविल अपील 1951. संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत अपील उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से मद्रास में न्यायपालिका (सुब्बा राव और वेंकटरामा) अय्यर जे. जे.) दिनांक 11 दिसंबर, 1951, रिट पेटी में 1951 का राज्य सं. 746। मामले के तथ्य और अधिवक्ता के बहस को निर्णय मे सम्पूर्णता मे शामिल किया गया है ।

अपीलार्थी की ओर से एन. राजगोपाल अयंगर।

आर. गणपति अय्यर, प्रथम उत्तरदाता के लिए।

एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी (जी. एन. जोशी, उनके साथ) भारत संघ के लिए।

के. ए. चिताले, महाधिवक्ता-मध्य भारत।

(जी. एन. जोशी, उनके साथ) मध्य भारत राज्य के लिए।

1952. 21 जनवरी। जे. फजल अली ने फैसला सुनाया। इस प्रकार है। पतंजलि शास्त्री सी. जे. ,, महाजन, मुखर्जी, दास और चंद्रशेखर अय्यर जे. जे. फजल से सहमत अली जे।

फजल अली जे.-यह एक आदेश से अपील है जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वरा दाखिल उत्प्रेषण लेख कि याचिका को खारिज किया है ।

अपीलार्थी उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने याचिका दायर की थी सलेम जिले के नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र से मद्रास विधान सभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र। 28 नवंबर, 1951 को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दायर नामांकन पत्रों की जांच की और उसी दिन उन्होंने अपीलार्थी के नामांकन पत्र को कुछ आधारों पर खारिज कर दिया, जिन्हें निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे इस अपील में उठाए गए बिंदु तक सामग्री नहीं हैं। इसके बाद अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और अनुरोध किया कि पुनरावर्तक अधिकारी के उनके नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करने और निर्वाचन अधिकारी को प्रकाशित होने वाले वैध नामांकनों की सूची में उनका नाम शामिल करने का निर्देश देने के लिए प्रमाण पत्र का एक रिट दायर किया जाए। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के पक्ष में दृष्टिकोण के कारण निर्वाचन अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस अपील में अपीलार्थी का तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही नहीं है, कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रभावित नहीं होती है संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) और यह कि वह मामले की परिस्थितियों में प्रमाणपत्र के रिट का हकदार था।

मोटे तौर पर, वे तर्क जिन पर उच्च न्यायालय के फैसले पर दो तरह से चुनौती दिया गया है:

(1) कि उच्च द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचा गया न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) की भाषा का अनुसरण नहीं करता है, चाहे वह अनुच्छेद स्वयं पढ़ा जाए या संविधान के भाग XV के अन्य अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए और

(2) कि विसंगतियाँ जो उत्पन्न होंगी यदि कोन अनुच्छेद 329 (ख) पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश स्वीकार किया जाता है, इतना चौंका देने वाला है कि अदालतों को अपीलार्थी की ओर से रखे गए निर्माण के पक्ष में झुकना चाहिए।

पहला तर्क जो निर्माण को चालू करता है अनुच्छेद 329 (ख) पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे तर्क का शुरुआत में ही संक्षिप्त रूप से निपटारा किया जा सकता है। यह कहा जाना चाहिए कि क्या अपील लांट विसंगति को कॉल करने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है कठिनाई या पूर्वाग्रह के रूप में वर्णित और उनका क्या प्रकृति को शक्तिशाली भाषा में कहा गया है वॉलेस जे. सर्वोत्तमा राव बनाम में। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, सैदापेट (1) इन शब्दों में:

" मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि चुनाव के बाद कोई भी उपाय है जो राहत देने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है टियोनर चाहते हैं, अर्थात्, कि यह चुनाव अब प्रकाशित हो रहना है, जब तक कि यह एक कैंडी के रूप में खुद के साथ आयोजित किया जा सकता है तिथि. उसे यह बताना कोई सांत्वना नहीं है कि वह खड़ा रह सकता है। किसी और चुनाव के लिए। उसे बताना कोई उपाय नहीं है। कि उन्हें चुनाव को चलने देना चाहिए और फिर इसे तय करना चाहिए याचिका द्वारा अलग करें और एक नए चुनाव का आदेश दें। नया चुनाव पूरी तरह से अलग हो सकता है परिस्थितियाँ और नई चीज़ों की एक श्रृंखला को आगे ला सकते हैं उम्मीदवार। याचिकाकर्ता के पास केवल अपना अधिकार हो सकता है यदि उनके बिना प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी जाती है तो राहत मिलेगी। जब तक उनका अस्वीकृत नामांकन बहाल नहीं हो जाता, और इसलिए इस चुनाव पर रोक लगाने का आदेश बिल्कुल आवश्यक था सैरी, जब तक कि मांगी गई राहत से उसे इनकार नहीं किया जाना था पूरी तरह से सीमित। इस तरह के ज्यादातर मामलों में नहीं संदेह है कि पीड़ित पक्ष के लिए कठिनाई होगी प्रतिबद्ध है; लेकिन जब वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, न्यायालय गलत की अनुमति देकर खुद को परेशान नहीं कर सकता है। जिसे वास्तव में उपभोग्य होने से रोकने के लिए कहा जाता है एड जबकि यह सूट की कोशिश करने में लगा हुआ है "।

हालाँकि ये अवलोकन केवल एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्तुत की गई तस्वीर और उसी विद्वान न्यायाधीश की बाद के मामले में तस्वीर का दूसरा पक्ष [देसी चेट्टियार वी. चिन्नासामी चेट्टियार (2)] निम्नलिखित में परिच्छेद:

"याचिकाकर्ता अपने उपचार के बिना नहीं है।

जिसके तहत समाधान चुनाव याचिका में निहित है-जो उसने पहले दाखिल कर दिया है। उसके तरफ से तर्क दिया गया है

(1) (1924) आई. एल. आर. 47 मद्रास। 585 600 पर।

(2) (1928) ए. आई. आर. मद्रास। 1271 1272 में।

कि वह उपाय जो उसे केवल एक बार हुए चुनाव को अलग रखने की अनुमति देता है, उतना प्रभावी नहीं है जितना कि एक जो उसे चुनाव को रोकने में सक्षम बनाएगा और पेज पर कुछ अवलोकन। 600 पेज का वोथामा राव बनाम अध्यक्ष, नगर परिषद, सैदापठ (1) उद्धृत किए गए हैं। सबसे पहले, हम नहीं देखते हैं कैसे केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को नहीं मिल सकता है चुनाव रुक गया और उसका उपाय उसके बाद ही है इन टिप्पणियों पर विचार करने के लिए निर्देशित किया गया था एक दीवानी मुकदमे में एक निषेधाज्ञा की औचित्य, ए जिस विषय से हम यहाँ संबंधित नहीं हैं। और अंत में यह देखा जा सकता है कि ये टिप्पणियां थीं कुछ साल पहले किया गया था जब व्यक्तियों का अभ्यास चुनाव रोकने के लिए आगे आ रहे हैं ताकि उनके आम है। यह स्पष्ट है कि इसका एक और पक्ष है विचार किए जाने वाले प्रश्न, अर्थात्, असुविधा चुनाव कराने के लिए लोक प्रशासन और स्थानीय बोर्डों का व्यवसाय रुका रहा जबकि व्यक्ति उनकी व्यक्तिगत शिकायतों पर मुकदमा चलाएँ। हम समझते हैं इस संघ में निर्वाचक सीटों के लिए चुनाव है इस याचिका के कारण 31 मई से रुका हुआ है, परिणाम यह है कि मतदाता असमर्थ रहे हैं तब से बोर्ड में कोई भी प्रतिनिधित्व होना, और बोर्ड काम कर रहा है, अगर वास्तव में यह काम कर रहा है अपने कुल के केवल एक नामित अंश के साथ शक्ति; और मामलों की यह स्थिति याचिकाकर्ता समर्थक अपनी व्यक्तिगत शिकायत तक जारी रहने का संकेत देता है वह संतुष्ट है "।

इन टिप्पणियों के संबंध में किया गया था स्थानीय बोर्डों के चुनाव अधिक बल के साथ लागू होंगे विधानमंडलों के चुनावों के लिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है यह दिखाने के लिए बहुत तर्क है कि एक देश में लोकतांत्रिक संविधान जिसमें विधायिकाएँ हैं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, यह गंभीर हो जाएगा परिणाम यदि चुनाव अनुचित रूप से लंबे समय तक चले या बाधित किया। इसके लिए, मामले का पहलू मुझे करना होगा बाद में विज्ञापन दें, लेकिन, यह वर्तमान उद्देश्य के लिए पर्याप्त है

(1) (1924) आई. एल. आर. 47 मद्रास। 585 600 पर।

सबसे पहले यह बताना कि इंग्लैंड में एक व्यक्तिगत उम्मीदवार को होने वाली कठिनाई और असुविधा को संसद को तत्काल राहत का प्रावधान करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त वजन नहीं माना गया है और पीड़ित उम्मीदवार ने को उनके नामांकन पत्र की अस्वीकृति की वैधता को चुनौती देने के लिए चुनाव के बाद तक प्रतीक्षा करें, और दूसरा, कि कठिनाई या असुविधा का सवाल आखिरकार केवल एक द्वितीयक सवाल है, क्योंकि यदि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अर्थ सही पाया जाता है, तो यह तथ्य कि इस तरह के निर्माण से कठिनाई और असुविधा होगी, अप्रासंगिक हो जाता है।

अनुच्छेद 329 संविधान के भाग XV का अंतिम अनुच्छेद है। विधान जिसका शीर्षक "चुनाव" है, और यह इस प्रकार चलता है: —

" इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद

(क) परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता निर्वाचन क्षेत्रों का गठन या किए जाने वाले या किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत, किसी भी अदालत में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा;

(ख) संसद के किसी भी सदन के लिए कोई चुनाव नहीं या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन को प्रश्न में बुलाया जाएगा, सिवाय उस निर्वाचन याचिका के जो ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई हो और जिसमें उपयुक्त विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के लिए, उसके द्वारा या उसके अधीन जो उपबंध किया जाए। इस लेख के अर्थ में, संदर्भ द्वारा दिया गया था

दोनों पक्ष एक ही भाग के अन्य अनुच्छेदों, अर्थात् अनुच्छेद 324 के लिए अपने तर्कों के दौरान, 325 , 326 , 327 और 328। अनुच्छेद 324 में प्रावधान है - निर्वाचन आयोग का गठन और नियुक्ति चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निदेशक को विधायिकाएँ; अनुच्छेद 325 भेदभाव को प्रतिबंधित करता है धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर मतदाताओं के खिलाफ या लिंग; अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार प्रदान करता है; लेख 327 संसद को कानून पारित करने का अधिकार देता है विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में दृष्टि, विषय

राज्य को शक्ति देने वाला एक पूरक अनुच्छेद है सभी के संबंध में प्रावधान करने के लिए विधानमंडल चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामले राज्य विधानमंडल। में एक उल्लेखनीय अंतर एक ओर अनुच्छेद 327 और 328 और दूसरी ओर अनुच्छेद 329 में उपयोग की जाने वाली भाषा यह है कि दो लेख "प्रो के अधीन" शब्दों से शुरू होते हैं। इस संविधान के दर्शन ", अंतिम अनुच्छेद शुरू होता है इन शब्दों के साथ "इसमें कुछ भी होने के बावजूद संविधान "। बार में यह स्वीकार किया गया कि भाषा में इस अंतर का प्रभाव यह है कि जबकि अनुच्छेद 327 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि, या अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडलों को बाहर नहीं किया जा सकता है के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता संविधान, उस अधिकार क्षेत्र को इस संबंध में बाहर रखा गया है अनुच्छेद 329 में उपबंधित मामलों के लिए।

अब, इन अपील केंद्रों में मुख्य विवाद अनुच्छेद 329 (बी) में "चुनाव याचिका के अलावा कोई चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा" शब्दों के अर्थ के आसपास, और यह तय करने की बात यह है कि क्या निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है। यह कहा जा सकता है कि नामांकन पत्र को "किसी भी चुनाव को प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा" शब्दों के भीतर समझा जा सकता है। अपीलार्थी का मामला यह है कि किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने से पहले जो कुछ हुआ है, उस पर सवाल उठाना चुनाव पर सवाल उठाने के समान नहीं है, और इस निर्माण के समर्थन में उसके होने पर दिए गए तर्क ये थे:

(1) कि लेख में "चुनाव" शब्द का उपयोग किया गया है 329 (ख) का अर्थ है कि इसका सामान्य और व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ क्या है, अर्थात्, मतदान का परिणाम या किसी उम्मीदवार का अंतिम चयन;

(2) कि एक चुनावी चुनाव याचिका ए के बाद मतदान के बाद ही दाखिल किया जा सकता है ऊपर या उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है, और क्या है? न ही इस तरह के द्वारा पूछताछ में बुलाया माली याचिका यह है कि अंतिम परिणाम, विवाद की पुष्टि करता है वह शब्द " अनुच्छेद 329 (बी) में चुनाव का मतदान के परिणाम या उम्मीदवार के अंतिम चयन के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता है।

(3) कि शब्द "से या संबंध में उत्पन्न होते हैं जिन शब्दों का उपयोग अनुच्छेद 324 (1) में किया गया है और जिन शब्दों का उपयोग अनुच्छेद 327 और 328 से संबंधित सभी मामलों के संबंध में या उनके साथ संयोजन में किया गया है, वे दर्शाते हैं कि संविधान के निर्माता जानते थे कि संदर्भ देते समय विभिन्न भाषाओं का उपयोग करना आवश्यक था। और क्रमशः उन मामलों के लिए जो मतदान के परिणाम के बाद होने से पहले होते हैं, और यदि वे अनुच्छेद 329 (बी) में निहित निषेध के दायरे में नामांकन पत्र की अस्वीकृति को शामिल करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने उस लेख में समान भाषा का उपयोग किया होगा; और

(4) कि निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित कारणों से नामांकन पत्र दाखिल करने पर सवाल उठाया जा सकता है: -लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 में नामांकन पत्रों की जांच और उनकी अस्वीकृति का प्रावधान किया गया है। पार्लियामेंट ने संविधान के अनुच्छेद 327 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रावधान किया है। जो "संविधान के प्रावधानों के अधीन" है। अतः निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र के अधीन है। अनुच्छेद 226 के अधीन।

ये तर्क पहली नजर में काफी प्रतीत होते हैं। प्रभावशाली, लेकिन मेरी राय में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में भारी और मूल रूप से अधिक महत्वपूर्ण तर्क हैं। जैसा कि हमने देखा है, निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनुच्छेद 329 (बी) में "चुनाव" शब्द का अर्थ दिया जाना है। यह शब्द लोकतांत्रिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में लंबे समय से उपयोग में है। व्यापक और संकीर्ण दोनों अर्थ। संकीर्ण अर्थ में, इसका उपयोग अंतिम चयन के लिए किया जाता है उम्मीदवार जो परिणाम को शामिल कर सकता है चुनाव तब होता है जब मतदान होता है या जब कोई चुनाव नहीं होता है तो किसी विशेष उम्मीदवार को निर्विरोध वापस कर दिया जाता है। में। व्यापक अर्थ में, इस शब्द का उपयोग पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो एक उम्मीदवार को घोषित करने में समाप्त होता है।

चुने गए। श्रीनिवासलु बनाम। कुप्पुस्वामी (1), विद्वान मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जाँच के बाद प्रश्न, राय व्यक्त की कि शब्द "चुनाव" यह पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए लिया जा सकता है। जहाँ एक "निर्वाचित सदस्य" द्वारा वापस किया जाता है, चाहे या मतदान करना आवश्यक नहीं पाया गया। इसके साथ विचार, मेरे भाई, महाजन जे. ने अपनी सहमति व्यक्त की सत नारायण बनाम। हनुमान प्रसाद (3); और मैं भी पाता हूँ। मैं खुद इससे सहमत हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव शब्द का उपयोग संविधान के भाग XV में किया गया है। व्यापक अर्थों में संविधान, अर्थात लौटने के लिए पूरी प्रक्रिया को नोट करें विधायिका के लिए एक उम्मीदवार। एक्सप्रे का उपयोग विशेष रूप से अनुच्छेद 324 में "चुनाव का संचालन" व्यापक अर्थ की ओर इशारा करता है, और वह अर्थ भी हो सकता है अन्य प्रावधानों में लगातार पढ़ा जाए जो यह अनुच्छेद 329 (बी) सहित भाग XV में होता है। कि "चुनाव" शब्द का यह व्यापक अर्थ है जब भी हम एक लोकतांत्रिक देश में चुनावों की बात की जाती है इस तथ्य से कि इस विषय पर अधिकांश पुस्तकों में और मामले से निपटने वाले कई मामलों में, एक सवाल यह है कि चुनाव कब शुरू होगा। द. हेल्सबरी में इस विषय को काफी संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित परिच्छेद (3) में इंग्लैंड के कानून शीर्षक "चुनाव की शुरुआत"

" हालांकि हर चुनाव में पहला औपचारिक कदम है रिट का मुद्दा, कुछ के लिए चुनाव पर विचार किया जाता है पहले की तारीख से शुरू करने का उद्देश्य। यह एक सवाल है वास्तव में प्रत्येक मामले में जब इस तरह का चुनाव शुरू होता है संबंधित पक्षों को जिम्मेदार बनाने का तरीका चुनाव कानून का उल्लंघन, परीक्षण यह है कि क्या प्रतियोगिता "यथोचित रूप से आसन्न" है। न ही मुद्दा न ही चुनाव की सूचना का प्रकाशन चुनाव की तारीख तय करने के रूप में देखा जा सकता है यह इस दृष्टिकोण से शुरू होता है। न ही, फिर से, करता है नामांकन का दिन किसी भी मानदंड को पूरा करता है। यह होगा चुनाव आमतौर पर कम से कम रिट जारी होने से पहले शुरू हो जाता है। चुनाव कब शुरू होगा, इस सवाल का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(1) (1928) ए. आई. आर. मद्रास। 253 255 पर।

(2)(1945) ए. आई. आर. लाहौर। 85

(3) हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के पृष्ठ 237, दूसरा संस्करण देखें, खण्ड 12।

यह उससे पूरी तरह से अलग है कि चुनाव का "संचालन और प्रबंधन" कब शुरू हुआ कहा जा सकता है। एक बार फिर, सवाल यह है कि कोई विशेष व्यक्ति कब उम्मीदवार बनने की शुरुआत एक ऐसा सवाल है जिसे प्रत्येक मामले में दरकिनार किया जाना चाहिए।

इस परिच्छेद की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि "चुनाव" शब्द का उपयोग पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में किया जा सकता है और उचित रूप से किया गया है जिसमें कई चरण होते हैं और कई चरण शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ का प्रक्रिया के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह है - सीमित आधार, उनमें से एक नामांकन पत्र का अनुचित पुनर्गठन है। जिस कानून से हम संबंधित हैं वह भौतिक रूप से अलग नहीं है, और हम पाते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 में, चुनाव घोषित करने का एक आधार है। शून्य होना नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव का कानून इस देश में विचार किया जाता है कि चुनाव कार्यवाही से जुड़े मामलों पर दो हमले होने चाहिए, एक जबकि वे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करके चल रहे हैं। संविधान का (सामान्य अधिकार क्षेत्र) न्यायालयों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है), और दूसरा। चुनाव के माध्यम से पूरा होने के बाद - यह याचिका। मेरी राय में, ऐसी स्थिति की पुष्टि करने के लिए यह संविधान के भाग XV और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की योजना के विपरीत होगा। जो, जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा लगता है कि कोई भी मामला जिसका चुनाव को दूषित करने का प्रभाव पड़ता है विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष केवल उचित स्तर पर उचित तरीके से लाया जाना चाहिए और किसी भी न्यायालय के समक्ष मध्यवर्ती स्तर पर नहीं लाया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कानून के तहत को अस्वीकार करना ही एकमात्र महत्व रखता है

एक नामांकन पत्र में यह तथ्य होता है कि इसका उपयोग चुनाव को विचाराधीन करने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है। अनुच्छेद 329 (बी) को स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि किस तरीके से और किस स्तर पर इस आधार पर और अन्य आधारों पर चुनाव कराने के लिए कानून कानून के तहत आग्रह किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह आवश्यक रूप से अनुसरण करता है इस प्रावधान की भाषा से प्लिकेशन कि उन आधारों का किसी अन्य मामले में आग्रह नहीं किया जा सकता है किसी भी अन्य स्तर पर और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष। यदि वे आधार जिनके आधार पर चुनाव बुलाया जा सकता है प्रश्न प्रारंभिक चरण में उठाया जा सकता है और त्रुटियाँ, यदि कोई सुधार किया जाता है, तो अधिनियम बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा। अनुच्छेद 329 (ख) जैसे प्रावधान को लागू करना और विशेष न्यायाधिकरण। इसके लिए जिम्मेदार कोई अन्य अर्थ लेख में उपयोग किए गए शब्द विसंगतियों का कारण बनेंगे, जिस पर संविधान विचार नहीं कर सकता था, उनमें से एक यह है कि परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते हैं उच्च न्यायालय द्वारा मतदान पूर्व चरण में और द्वारा चुनाव न्यायाधिकरण, जो एक स्वतंत्र होना है शरीर, उस स्तर पर जब मामला उठाया जाता है उससे पहले।

मुझे लगता है कि योजना की एक संक्षिप्त परीक्षा संविधान और प्रतिनिधित्व का भाग XV लोक अधिनियम, 1951 का अर्थ यह होगा कि मैंने जो सुझाव दिया है वह सही है। मोटे तौर पर बोलने से पहले, एक चुनाव तंत्र लाया जा सकता है संचालन में, तीन आवश्यकताएँ हैं जिनकी आवश्यकता होती है उपस्थित होने के लिए, अर्थात्, (1) का एक समूह होना चाहिए सभी के संबंध में प्रावधान करने वाले कानून और नियम बनाया जाना है; (2) एक कार्यकारी होना चाहिए के उचित आचरण को सुरक्षित करने के कर्तव्य के साथ आरोपित चुनाव; और (3) एक न्यायिक न्यायाधिकरण होना चाहिए। उत्पन्न या संबंधित विवादों से निपटने के लिए चुनावों के साथ। अनुच्छेद 327 और 328 पहले से संबंधित हैं। इन अनिवार्यताओं में से, अनुच्छेद 324 दूसरे के साथ और अनुच्छेद 329 तीसरी अपेक्षा के साथ। बाकी दो भाग XV में लेख, अर्थात। , अनुच्छेद 325 और 326, सौदा सिद्धांत के दो मामलों के साथ जिनके लिए संविधान राष्ट्र-निर्माताओं ने बहुत महत्व दिया है। वे.

ये हैं: -(1) में भेदभाव के खिलाफ निषेध इसमें शामिल करने के लिए तैयारी या पात्रता धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची या उनमें से कोई भी; और (2) वयस्क मताधिकार। का भाग XV संविधान वास्तव में अपने आप में एक संहिता प्रदान करता है पूरा आधार-उचित अधिनियमन के लिए काम करें कानून और संचालन के लिए उपयुक्त मशीनरी की स्थापना चुनाव।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद द्वारा अनुच्छेद 327 के तहत पारित किया गया था संविधान, के संबंध में विस्तृत प्रावधान करता है चुनाव से जुड़े सभी मामले और सभी चरण इस देश में विभिन्न विधानसभाएँ। वह अधिनियम है 11 भागों में विभाजित, और यह देखना दिलचस्प है विभिन्न प्रकार के विषयों से वे निपटते हैं। भाग-II के लिए योग्यता और अयोग्यताओं से संबंधित है सदस्यता ", भाग III की अधिसूचना से संबंधित है आम चुनाव, भाग IV प्रशासन के लिए प्रावधान करता है चुनाव के संचालन के लिए प्रत्यावर्ती तंत्र, और भाग 5 के वास्तविक आचरण के लिए प्रावधान करता है चुनाव और प्रस्तुति जैसे मामलों से संबंधित नामांकन पत्रों की, एक वैध नामांकन की आवश्यकताएँ नामांकनों की जांच, आदि, और इसके लिए प्रक्रिया मतदान और मतों की गिनती। भाग VI से संबंधित है चुनावों के संबंध में विवाद और प्रावधान चुनाव याचिकाओं को प्रस्तुत करने का तरीका चुनाव न्यायाधिकरणों का गठन और चुनाव का परीक्षण याचिकाएँ। भाग VII विभिन्न भ्रष्ट और अवैध प्रथाएँ जो चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं, और चुनावी अपराध। जाहिर है, यह अधिनियम एक आत्म-विश्वास है जहाँ तक चुनावों का संबंध है, संरेखित अधिनियम, जिसका अर्थ है कि जब भी हमें पता लगाना है संबंधित किसी भी मामले के संबंध में वास्तविक स्थिति चुनाव, हमें केवल अधिनियम और नियमों को देखना है। इसके तहत बनाया गया। अधिनियम के प्रावधान जो हैं - वर्तमान चर्चा के लिए सामग्री हैं धारा 80, चुनाव याचिकाओं के रूप से संबंधित भाग IV, उनकी सामग्री और राहत जो मांगी जा सकती हैं उन्हें। धारा 80, जिसका मसौदा लगभग उसी में तैयार किया गया है अनुच्छेद 329 (बी) के रूप में भाषा में प्रावधान है कि "कोई चुनाव नहीं" एक चुनाव उच्च न्यायालय रिपोर्ट को छोड़कर प्रश्न में बुलाया जाएगा

इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत याचिका। धारा 100, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्रावधान उन आधारों पर विचार करता है जिन पर चुनाव हो सकता है प्रश्न में बुलाया गया, जिनमें से एक अनुचित रीसेक है एक नामांकन पत्र। धारा 105 में कहा गया है कि रा " इस अधिनियम के तहत किए गए न्यायाधिकरण के प्रत्येक आदेश को. अंतिम और निर्णायक बनें "। धारा 170 में प्रावधान है कि " किसी भी दीवानी अदालत को सवाल करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। की गई किसी कार्रवाई या किसी निर्णय की वैधता निर्वाचन अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के तहत नियुक्त यह "। चुनाव के संबंध में ये मुख्य प्रावधान हैं। जिन मामलों को न्यायिक रूप से निपटाया जा रहा है, और उन्हें ध्यान दें कि कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है प्रभाव कि चुनाव से जुड़ी कुछ भी हो सकती है मध्यवर्ती स्तर पर पूछताछ की जाती है।

यह अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जहां अधिकार का अधिकार है बैलिटी एक क़ानून द्वारा बनाई जाती है जो एक विशेष अधिकार देता है इसे लागू करने के लिए उपाय, उसके द्वारा प्रदान किया गया उपाय केवल कानून का लाभ उठाया जाना चाहिए। यह नियम बताया गया था वूल्वरहैम्प्टन में जे. विल्स द्वारा बहुत स्पष्टता के साथ न्यू वाटर वर्क्स कं. वी. हॉक्सफोर्ड (1) निम्नलिखित में परिच्छेद:

" तीन प्रकार के मामले हैं जिनमें देयता होती है। कानून के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। एक है, जहाँ सामान्य कानून में कोई दायित्व मौजूद था, और उस दायित्व की पुष्टि एक क़ानून द्वारा की जाती है जो देता है उपचार का एक विशेष और विशिष्ट रूप उपचार जो मौजूद था कानून; वहाँ, आम जब तक कि क़ानून में ऐसे शब्द न हों जो स्पष्ट रूप से या द. आवश्यक निहितार्थ द्वारा बहिष्कृत सामान्य कानून उपाय, मुकदमा करने वाली पार्टी के पास आगे बढ़ने के लिए अपना चुनाव है या तो वह या वैधानिक उपाय। द्वितीय श्रेणी केवल, लेकिन उपचार का कोई विशेष रूप प्रदान नहीं करता है: वहाँ, पार्टी केवल कॉम पर कार्रवाई करके आगे बढ़ सकती है मोन कानून। लेकिन एक तीसरा वर्ग है, अर्थात। , कहाँ ए सामान्य कानून में मौजूद दायित्व एक द्वारा बनाया गया है कानून जो एक ही समय में एक देता है विशेष और इसका उपाय इसे लागू करने के लिए विशेष उपाय। कानून द्वारा प्रदान किया गया पालन किया जाना चाहिए, और यह नहीं है

(1) 6 सी. बी. (एनएस) 336,356।

पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के लिए सक्षम द्वितीय श्रेणी के मामलों के लिए केबल। द्वारा दिया गया प्रपत्र कानून को अपनाया जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए।

इस परिच्छेद में निर्धारित नियम को मंजूरी दी गई थी नेविल बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा। लंदन एक्स प्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड (1) और इसकी पुष्टि की गई है प्रिवी काउंसिल इन अटॉर्नी द्वारा-ट्राई के जनरल निदाद और टोबैगो बनाम। गॉर्डन ग्रांट एंड कंपनी (2) और राज्य सचिव वी। मास्क एंड कंपनी (3); और यह भी किया गया है अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समान रूप से लागू होना: हुर्दुतराई वी. देखें। कलकत्ता का आधिकारिक कार्यभार (*)। ऐसा होने पर, मुझे लगता है कि यह एक उचित अनुमान होगा। के प्रतिनिधित्व के प्रावधानों से लोक अधिनियम में कहा गया है कि अधिनियम में केवल एक का प्रावधान है उपाय, वह उपाय एक चुनाव याचिका द्वारा किया जा रहा है चुनाव समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाए, और कोई नहीं है किसी भी मध्यवर्ती चरण में उपचार प्रदान किया जाता है।

यह तर्क दिया गया था कि प्रतिनिधित्व के बाद से लोक अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिनियमित किया गया था संविधान, यह अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं कर सकता है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करेगा संविधान। हालाँकि यह तर्क पूरी तरह से है अधिनियम को अनुच्छेद 329 (बी) के साथ पढ़कर समाप्त करें। यह ध्यान दिया जाएगा कि उस लेख में उपयोग की गई भाषा और अधिनियम की धारा 80 में लगभग समान है, यह अंतर केवल इतना है कि लेख से पहले इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद शब्द यह "। मुझे लगता है कि वे शब्द पूर्व के लिए काफी उपयुक्त हैं उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से निपटने के लिए कोई भी मामला जो चुनाव के दौरान उत्पन्न हो सकता है प्रगति।

यह कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि की धारा 107 (1) लोक अधिनियम, 1949 (12 और 13 जी. ई. ओ.) 6 , सी। 68) में इंग्लैंड का मसौदा लगभग अनुच्छेद 329 (बी) के समान भाषा में तैयार किया गया है। वह खंड इस प्रकार है:" कोई संसदीय चुनाव नहीं और पार में कोई वापसी नहीं इस अधिनियम के इस भाग के अनुसार प्रस्तुत अनुचित चुनाव या अनुचित वापसी (यहां संसदीय चुनाव याचिका के रूप में संदर्भित) की याचिका के अलावा देयता पर सवाल उठाया जाएगा।

(1) [1919] ए. सी. 368 (3) (1940) 44 सी. डब्ल्यू. एन. 709.

(2) [1935] ए. सी. 532 (4) (1948) 52 सी. डब्ल्यू. एन. 343,349।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की भाषा का उपयोग किया गया था इससे पहले के कानून, और यह उल्लेखनीय है कि इसने कभी नहीं किया है एन. पी. पोंट नामांकन पत्र एक रिट का विषय हो सकता है सर्टिओरारी या मैंडमस। दूसरी ओर, यह था बार में स्वीकार किया कि अनुचित री का सवाल नामांकन पत्र का विभाजन हमेशा निर्वाचन क्षेत्र में लाया गया है उस देश में उपयुक्तन्यायाधिकरण के समक्ष के समापन के बाद एक चुनाव याचिका का साधन चुनाव। यह सच है कि कोई सीधा निर्णय नहीं होता है अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रासंगिक प्रावधानों में उपयोग किए गए शब्द ए. पी. जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करें एक मध्यवर्ती चरण में विशेषाधिकार रिटों का स्वामित्व चुनाव, लेकिन इस तरह के किसी भी निर्णय की पूर्ण अनुपस्थिति केवल इस दृष्टिकोण पर हिसाब किया जा सकता है कि विचाराधीन सायनों को आम तौर पर समझा गया है उस प्रभाव को। हमारा ध्यान नियम 13 की ओर आकर्षित किया गया था 1872 के मतपत्र अधिनियम से जुड़े नियम और एक समान 1949 के संसदीय चुनाव नियमों में नियम, बशर्ते कि निर्वाचन अधिकारी का निर्णय नामांकन पत्र पर आपत्ति की अनुमति न देना अंतिम होगा, लेकिन इसकी अनुमति देना इसके अधीन होगा चुनाव या पुनः चुनाव पर सवाल उठाने वाली याचिका पर प्रत्यावर्तन ये नियम लेकिन प्रभावित न करें। मुख्य बात मुड़ें। मुझे लगता है कि यह वैध रूप से कहा जा सकता है कि तर्क। यदि अनुच्छेद 329 (ख) में उपयोग किए गए शब्दों के समान शब्द हैं इंग्लैंड में लगातार उपयुक्त शब्दों के रूप में व्यवहार किया गया न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करना जिसमें शामिल हैं - उच्च न्यायालय, उसी परिणाम का पालन करना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) में उपयोग किए गए शब्द। शब्द "कुछ भी होने के बावजूद" यह में संविधान "उस अनुच्छेद को समान व्यापक और एक संप्रभु कानून द्वारा पारित क़ानून के रूप में बाध्यकारी प्रभाव अंग्रेजी संसद की तरह।

यह इंगित किया जा सकता है कि अनुच्छेद 329 (बी) उस लेख के खंड (ए) के पूरक के रूप में पढ़ें। खंड (ए) न्यायालयों की अधिकारिता को प्रतिबंधित करता है - ऐसी विधि के संबंध में जो अनुच्छेद 327 के अधीन बनाई जाए। और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित 328 हमारे समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि अनुच्छेद 329 (बी) के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता मामले

मतदान की शुरुआत के बीच उत्पन्न होने वाले और अंतिम चयन। वह प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए विधायिका के पास क्या संभावित कारण हो सकता है केवल नामांकन से जुड़े मामलों को छोड़ना पड़ा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन संविधान का अनुच्छेद 226। यदि भाग XV संविधान अपने आप में एक संहिता है, यानी यह अधिकारों का निर्माण करता है। और एक विशेष द्वारा उनके प्रवर्तन के लिए प्रावधान करता है सहित सभी न्यायालयों के बहिष्कार के लिए न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय, यह मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि संविधान ने चुनाव के पक्ष में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया उपकर को विषय बनाया जाएगा-पहले प्रतियोगिता का विषय उच्च न्यायालयों ने और इस तरह समय-अनुसूची को बाधित कर दिया चुनावों के बारे में। अधिक उचित दृष्टिकोण प्रतीत होता है मान लीजिए कि अनुच्छेद 329 में सभी "चुनावी मामले" शामिल हैं।

जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं वे हो सकते हैं - संक्षेप में संक्षेप में इस प्रकार है:

(1) महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखना जिसे विधायिकाओं को लोकतांत्रिक तरीके से करना होता है एक होना देशों में, इसे हमेशा मान्यता दी गई है होना चाहिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के अनुसार जितनी जल्दी हो सके निष्कर्ष निकाला गया अनुसूची और सभी विवादास्पद मामलों और चुनावों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को बाद तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। चुनाव समाप्त हो गए हैं, ताकि चुनाव की कार्यवाही अनावश्यक रूप से मंद या लंबी न हो।

(2) इस सिद्धांत के अनुरूप, योजना इस देश में चुनाव कानून के साथ-साथ इंग्लैंड में भी भूमि यह है कि किसी भी ऐसी चीज का कोई महत्व नहीं होना चाहिए जो "चुनाव" को प्रभावित नहीं करती है; और यदि कोई अनियमितताएं की जाती हैं, जबकि यह प्रगति पर है और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित हैं, जो उस कानून के तहत, जिसके द्वारा चुनाव शासित होते हैं, "चुनाव" को दूषित करने का प्रभाव डालेंगे और प्रभावित व्यक्ति को इसे प्रश्न में बुलाने में सक्षम बनाएगा, तो उन्हें चुनाव याचिका के माध्यम से एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए और चुनाव के दौरान किसी भी अदालत के समक्ष विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

इस स्तर पर निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

थेबर्गे बनाम में प्रिवी काउंसिल का। लाउड्री (1)। द.

(1) (1876) 2 ऐप. कैस। 102 .

उस मामले में याचिकाकर्ता को विधिवत घोषित किया गया था में एक चुनावी जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य चुना गया क्यूबेक प्रांत की विधान सभा, बाद में, याचिका पर, अमान्य घोषित किया गया था उनका चुनाव और उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा शून्य, के तहत क्यूबेक परिवर्तित चुनाव अधिनियम, 1875, और स्वयं को भ्रष्ट प्रथाओं का दोषी घोषित किया, दोनों व्यक्तिगत रूप से और उसके एजेंटों द्वारा। इसके बाद उन्होंने आवेदन किया। परिषद में महामहिम से अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए, लेकिन यह इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि मेला 1875 के अधिनियम और 1872 के अधिनियम का निर्माण जो इससे पहले अन्य चीजों के साथ प्रदान करता था कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अनिश्चित नहीं होगा। अपील की संभावना "यह थी कि इसका इरादा था चुनाव याचिकाओं का इस तरह से परीक्षण करना चाहिए कि अपने निर्णय को सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम बनाना चाहिए और इसके निर्णय की घटना को इसके साथ नहीं जोड़ा जा रहा है क्राउन द्वारा अपने विशेषाधिकार के तहत समीक्षा की गई। में। प्रिवी काउंसिल का निर्णय देते हुए, प्रभु कैर्न्स ने निम्नलिखित रूप में देखा: —

" संसद के ये दो अधिनियम, 1872 और 1875, अधिनियम अपने चरित्र में विशिष्ट हैं। वे गठन या प्रावधान करने वाले अधिनियम नहीं हैं केवल सामान्य नागरिक अधिकारों का निर्णय; वे अधिनियम एक पूरी तरह से नए का निर्माण कर रहे हैं, और उस तक समय अज्ञात, किसी विशेष न्यायालय में अधिकार क्षेत्र..... बाहर निकालने के उद्देश्य से, अपने स्वयं के साथ विधान सभा की सहमति, और निहित वह न्यायालय, वह बहुत ही विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो, ऊपर उस समय तक, विधान सभा में मौजूद था चुनाव याचिकाओं पर निर्णय लेना और उनका निर्धारण करना उन लोगों की स्थिति जिन्होंने सदस्य होने का दावा किया अत्यंत विशेष, और स्पष्ट घटनाओं में से एक या ऐसी अधिकारिता के परिणाम यह होने चाहिए कि - यथासंभव निर्णायक बन जाता है और स्थिरांक को सक्षम बनाता है। विधान सभा का गठन स्पष्ट रूप से और जल्दी से जाना जाता है। ”

कुछ अन्य मामलों से निपटने के बाद, माननीय कुलाधिपति निम्नलिखित टिप्पणियाँ करने के लिए आगे बढ़े:

" अब, विषय-वस्तु, जैसा कि कहा गया है, कानून अत्यंत विशिष्ट है। यह चिंता की बात है निर्वाचकों और विधान सभा के अधिकार और विशेषाधिकार, जिसके लिए वे सदस्यों का चुनाव करते हैं। उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को हमेशा हर उपनिवेश में, मातृ देश के उदाहरण का पालन करते हुए, विधान सभा द्वारा ईर्ष्या से बनाए रखा गया है और उनकी रक्षा की गई है। इन सबसे ऊपर, उन्हें उन अधिकारों और विशेषाधिकारों के रूप में देखा गया है जो क्राउन की पूर्ण स्वतंत्रता में विधान सभा से संबंधित हैं, जहां तक वे उचित रूप से मौजूद हैं। और यह कुछ हद तक आश्चर्यजनक परिणाम होगा, और शायद ही कानून की सामान्य योजना के अनुरूप होगा, अगर, इस तरह के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में, यह पाया जाता है कि अंतिम उपाय में उनका निर्धारण अब विधान सभा का नहीं था। अब वह उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं था जिसे विधान सभा ने अपने स्थान पर रखा था, लेकिन क्राउन इन काउंसिल से संबंधित था, घर पर क्राउन के सलाहकारों की सलाह के साथ, जिसका निर्धारण विधान सभा के निर्णय या उस न्यायालय के संदर्भ के बिना किया जाना था, जिसे विधान सभा ने अपने निर्णय में प्रतिस्थापित किया था। जगह "।

इस निर्णय से जो बिंदु सामने आ सकते हैं वे हैं - निम्नलिखित रूप में वर्णित है: --

(1) उम्मीदवार के रूप में मतदान करने या खड़े होने का अधिकार चुनाव एक नागरिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानून या विशेष कानून का एक हिस्सा है और इसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होना चाहिए।

(2) कड़ाई से कहें तो यह एकमात्र अधिकार है विधायिका सभी मामलों की जांच और निर्धारण करेगी अपने सदस्यों के चुनाव से संबंधित, और यदि विधायिका इसे अपने हाथों से लेती है और एक में निहित होती है न्यायशास्त्र विशेष न्यायाधिकरण एक पूरी तरह से नया और अज्ञात में अभ्यास किया कि विशेष अधिकारिता होनी चाहिए उस कानून के अनुसार जो इसे बनाता है।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रश्न के रूप में अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की क्या शक्तियां हो सकती हैं, यह एक उचित अवसर पर तय किया जाना चाहिए।

इस स्तर पर एक तर्क का उल्लेख करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 71 (1) की भाषा पर आधारित अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष पेश किया गया। यह प्रावधान इस प्रकार है: --

" संघ से या उससे उत्पन्न होने वाले सभी संदेह और विवाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ संबंध की जांच और निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय जिसका निर्णय अंतिम होगा।

तर्क इस प्रकार था। वहाँ एक चिह्नित है अनुच्छेद 71 (1) और अनुच्छेद 329 (बी) में उपयोग की गई भाषा के बीच विरोधाभास। दोनों प्रावधानों में प्रयुक्त वाक्यांश विज्ञान में अंतर से पता चलता है कि उनका उद्देश्य उन मामलों के संबंध में समान अर्थ और दायरा रखना नहीं हो सकता था जिन्हें वे क्रमश: उन न्यायाधिकरणों के समक्ष लाएंगे जिनसे वे निपटते हैं। यदि संविधान के निर्माता, जो स्पष्ट रूप से खुद को व्यक्त करना जानते थे, अनुच्छेद 329 (बी) के दायरे में विधानसभाओं के चुनावों से जुड़े सभी संभावित विवादों को शामिल करने का इरादा रखते थे, जिनमें शामिल हैं - नामांकन के बारे में विवाद होने पर, उन्होंने अनुच्छेद 71 (1) में पाए जाने वाले समान शब्दों का उपयोग किया होगा। यह सच है कि प्रत्येक प्रावधान में समान भाषा का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति के विभिन्न वैकल्पिक तरीकों की कल्पना की जा सकती है जो व्यक्त करेंगे। अधिक स्पष्ट और उचित रूप से अनुच्छेद 329 (बी) में क्या कहा गया है पहुँचाने के लिए।

मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यह स्वीकार किया जाता है कि एक ही विचार को अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है और एक ही वाक्यांश को प्रत्येक समर्थक दृष्टि में नियोजित करने की आवश्यकता नहीं है, तर्क अपनी अधिकांश शक्ति खो देता है। लेकिन, हालाँकि ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है कि इस बारे में एक अच्छी व्याख्या है कि अनुच्छेद 329 (बी) का मसौदा क्यों तैयार किया गया था।

चुनाव नियमों के तहत बनाए गए का एक संदर्भ 1919 और 1935 के भारत सरकार के अधिनियमों से पता चलेगा कि इस विषय पर उनमें प्रावधान अनुच्छेद 329 (बी) के समान ही थे।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत बनाया गया संबंधित नियम चुनावी नियमों का नियम 31 था, और यह निम्नानुसार चलता है:

" प्रश्न में कोई चुनाव नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय इसके इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत एक चुनाव याचिका।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह नियम भाग VII में आता है, जिसका शीर्षक है "चुनाव की वैधता के बारे में संदेह और विवादों का अंतिम निर्णय"। ये शब्द उस कार्य पर कुछ प्रकाश डालते हैं जो चुनाव न्यायाधिकरण को करना था, और ये वही शब्द हैं जो विद्वान अपीलार्थी के लिए सलाह देते हैं। तर्क दिया, इसका उपयोग अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए था।

नियम चुनाव में भी यही योजना अपनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया, 1935 , जो "भारत सरकार" में निहित हैं चुनाव (प्रांतीय चुनाव) (भ्रष्ट आचरण और याचिकाएँ) आदेश, 1936 ", दिनांक 3 जुलाई, 1936। में। वह आदेश, पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत नियम 31 के अनुरूप नियम, इस प्रकार चलता है: --

" इसके अलावा कोई चुनाव नहीं बुलाया जाएगा के अनुसार प्रस्तुत एक चुनाव याचिका आदेश के इस भाग के प्रावधान।

यह नियम आदेश के भाग III में पाया जाता है, चुनाव की वैधता और अयोग्यता के बारे में भ्रष्ट प्रथाएँ "।

जिन नियमों का मैंने उल्लेख किया है वे स्पष्ट रूप से थे संबंधित प्रावधानों के प्रारूप पर तैयार किया गया 1868 और 1872 के ब्रिटिश अधिनियमों का, और उन्हें के रूप में एक ही जमीन को कवर करने का इरादा है इंग्लैंड में प्रावधानों को कवर करने के लिए समझा गया है इतने सालों से उस देश में। अगर भाषा अनुच्छेद 329 (ख) में प्रयुक्त को इसके विरुद्ध माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसे देखना मुश्किल नहीं होना चाहिए संविधान निर्माताओं ने उस प्रो को क्यों तैयार किया अपने वर्तमान रूप में दृष्टि और भाषा का चयन किया जिनका लगातार कुछ पहले उपयोग किया गया था विधायी प्रावधान और जो की कसौटी पर खड़े थे समय।

और अब एक शब्द है कि नकारात्मक भाषा क्यों थी अनुच्छेद 329 (ख) में प्रयुक्त। मुझे ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 71 (1) और अनुच्छेद 329 (बी) के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद 71 (1) को एक प्रासंगिक रूप में होना था, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकारिता प्रदान करता है जिसका प्रयोग वह न्यायालय इस अनुच्छेद के अलावा नहीं कर सकता था। दूसरी ओर, अनुच्छेद 329 (बी) का मुख्य उद्देश्य चुनाव के संबंध में सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना या हटाना था। मामला और एकमात्र तरीका निर्धारित करना जिसमें चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए नकारात्मक रूप अधिक उपयुक्त था, और ऐसा होने पर, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पहले से मौजूद पैटर्न का पालन करने का निर्णय लिया गया था जिसमें नकारात्मक भाषा को भी अपनाया गया था।

निष्कर्ष निकालने से पहले, मुझे एक तर्क का उल्लेख करना चाहिए जिसे विद्वान वकील ने बहुत जोर से दबाया था अपीलार्थी के लिए और जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने इन शब्दों में पुनः प्रस्तुत किया है:

" इसके बाद यह तर्क दिया गया कि यदि नामांकन हिस्सा है चुनाव की वैधता के बारे में विवाद चुनाव से संबंधित एक विवाद है और जिस पर केवल अनुच्छेद 329 (बी) के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त न्यायाधिकरण को एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करके सवाल उठाया जा सकता है और यह कि निर्वाचन अधिकारी को उस मामले को तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, और यह आगे तर्क दिया गया कि धारा 36 1951 का अधिनियम XLIII उतला अधिकार होगा क्योंकि यह निर्वाचन अधिकारी को एक अधिकारिता प्रदान करता है जो अनुच्छेद 329 (बी) एक न्यायाधिकरण को नियुक्त करने के लिए प्रदान करता है लेख के अनुसार "।

यह तर्क महान द्वंद्वात्मक सरलता को प्रदर्शित करता है, लेकिन इस अपील के परिणाम पर इसका कोई असर नहीं है और मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत जल्द दिया जा सकता है। के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के तहत निर्वाचन अधिकारी का कर्तव्य है कि वह इसकी जांच करे। नामांकन पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करते हैं और किसी भी नामांकन पर की जाने वाली सभी आपत्तियों का निर्णय लेते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक इस कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी संख्या उम्मीदवार बिना अनुपालन के चुनाव में खड़े हो सकते हैं अधिनियम के प्रावधानों और के एक बड़े सौदे के साथ

भ्रम पैदा हो सकता है। उन पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में, निर्वाचन अधिकारी किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाता है। नामांकन पत्रों की जांच केवल एक चरण है, हालांकि चुनाव प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण चरण है। यह चुनाव पूरा होने से पहले किए जाने वाले आवश्यक कर्तव्यों में से एक है, और चुनाव की कार्यवाही पूरी होने की दिशा में की गई किसी भी बात को किसी भी तर्क से चुनाव पर सवाल उठाने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। तर्क की भ्रांति इस बात में निहित है कि चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए एक कदम को चुनाव के बराबर माना जाता है। हालाँकि इस अपील का निर्णय एकल शब्द "चुनाव" के निर्माण पर नहीं है, बल्कि समग्र अभिव्यक्ति के निर्माण पर है-"कोई चुनाव नहीं होगा। संविधान के भाग XV और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की योजना को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए इसके संदर्भ और सेटिंग में प्रश्न में रखा गया है। हालांकि, इस तर्क का इस अपील में पूछे गए प्रश्न के दृष्टिकोण के इस तरीके से कोई लेना-देना नहीं है, जो मुझे एकमात्र सही तरीका लगता है। जानकारी दी कि मद्रास उच्च न्यायालय के अलावा हम हैं। न्यायालय, सात अन्य राज्य उच्च न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि उनके पास अनुचित के संबंध में याचिकाओं पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नामांकन पत्रों की अस्वीकृति। इस दृश्य में है

मेरा राय सही है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। इसलिए अपील को विफल होना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए इस अपील में उठाए गए बिंदुओं की प्रकृति और महत्व, लागत के लिए कोई आदेश नहीं होना चाहिए।

मुखर्जी जे.-मैं सहमत हूँ। दास जे-मैं सहमत हूँ।

जे. चंद्रसेखर अय्यर-मैं सहमत हूँ।

याचिका खारिज कर दी गई।

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ता: एस. सुब्रमण्यम।

प्रथम उत्तरदाता के लिए अभिकर्ता: पी. ए. मेहता
भारत संघ और राज्य के लिए एजेंट मध्य भारत: पी. ए. मेहता